(b) what are the guidelines provided by the Bureau of Public Enterprises to the Public Undertakings on the employee-employer relationship ;

(c) whether the Public Sector Undertakings are following vigorously the guidelines of BPE, with the reasons therefor ;

(d) what action Government propose to take, in case these guidelines of employee-employer relationship are ignored by some undertakings, with the reasons therefor ; and

(e) whether Government propose to suggest where the employees are the victims of the non-applying of employee-employer relationship by the undertakings ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY) (SHRIMATI KRISHNA SAHI) :

(a) The employee-employer relationship in Public Sector Undertakings is governed by various Industrial Laws enacted by the Ministry of Labour.

(b) to (e) Do not apply.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

3234. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से वित्तीय सुधारों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप किन-किन उपक्रमों को लाभ हुआ है ; और

(ग) इस कदम से गत वर्ष उपक्रमों की उत्पादन क्षमता में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ?

उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जुलाई, 1991 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में सरकारी उद्यमों के कार्यनिष्पादन में सुधार करने हेतु समग्र सुधारों से सम्बन्धित नीति का उल्लेख है जिनकी परिगणना लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1991-92 के खण्ड 1, पृष्ठ संख्या 3 पर की गई है जिसे 26-2-93 को संसद में रखा गया था । वित्तीय सुधार, इस सम्बन्ध में की गई समग्र कार्रवाई का एक भाग है । पृथक-पृथक उद्यमों के उत्पादन सम्बन्धी कार्य-निष्पादन में सुधार का विवरण उपरोक्त खण्ड के वि० 144 से वि० 161 पर दिया गया है । बहरहाल उद्यम विशेष के समग्र कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकारी क्षेत्र के संबद्ध उपक्रमों और प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

भारत में विदेशी पूंजी का निवेश

3235. **श्री अजीत जोगी** :
चौधरी हरि सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 में औद्योगिक क्षेत्र में कुल कितनी विदेशी पूंजी का निवेश किया गया है; और

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान कितनी विदेशी पूंजी के आगम का अनुमान है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री और उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) वर्ष 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की इक्विटी पूंजी में विदेशी निवेश की अनुमोदित राशि निम्नलिखित है :-

वर्ष	विदेशी निवेश की अनुमोदित राशि (रुपये करोड़ में)
1990-91	137.10
1991-92	1328.19
1992-93	5611.06

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि 1993 (जनवरी से मई) में भारतीय कंपनियों की शेयर पूंजी में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का वास्तविक आगम अनुमानतः 736.53 करोड़ रुपये है ।

खादी संस्थाओं संबंधी सोंधिया समिति की सिफारिशें

3236. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खादी संस्थाओं और खादी कर्मियों के दरपेश आ रही कठिनाइयों के निवारण के लिये उपाय सुझाने हेतु सोंधिया समिति की नियुक्ति की गयी थी और क्या सरकार को सोंधिया समिति की सिफारिशें प्राप्त हो गयी हैं,

(ख) यदि हां, तो सोंधिया समिति की सिफारिशें क्या हैं, और